अच्छे कर्म ही इंसान को दूसरों से अलग और मूल्यवान बनाते है।
– अज्ञात

सियासी प्रयोग की शुरुआत

महाराष्ट्र में देखने की बात यह होगी कि तीनों सहयोगी दल एक–दूसरे के स्पेस का ख्याल रख पाते हैं या नहीं। इसी तरह तीनों दलों के नेताओं में कितना समन्वय रह पाता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी।

अरविंद जोशी

महाराष्ट्र में लंबे राजनीतिक ड्रामे के बाद शिवसेना–एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन गई है। यह सिर्फ एक नई सरकार का बनना नहीं है बल्कि एक नए तरह के सियासी प्रयोग की शुरुआत भी है। तीनों दलों ने सरकार बनाने से पहले बाकायदा अपने गठबंधन के नाम का ऐलान किया और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जारी कर दिया। यह गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' कहलाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा गया है कि गठबंधन संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। इसमें किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं। कह सकते हैं कि देश में गठबंधन राजनीति अपने एक नए दौर में प्रवेश कर रही है।

इस दौर में पोस्ट–पोल अलायंस ज्यादा मायने रख रहा है। हाल में कई ऐसे उदाहरण देखे गए कि जिन पार्टियों ने एक–दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाद में उन्होंने मिलकर सरकार बना ली। कर्नाटक और हरियाणा इसका ताजा उदाहरण हैं। रिश्ते अब सत्ता के समीकरण के आधार पर बन रहे हैं, सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर नहीं। दो भिन्न विचारधाराओं वाले दलों ने पहले भी गठबंधन किया है, इसलिए इस एतराज में कोई खास दम नहीं है कि शिवसेना और कांग्रेस दो अलग–अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिहार में जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार थोड़े–थोड़े समय बाद यह जताने से नहीं चूकते कि उनके विचार बीजेपी से अलग हैं लेकिन बिहार के हित के लिए वे उसके साथ हैं। बीजेपी ने जम्मू–कश्मीर और नॉर्थ–ईस्ट में विपरीत विचार वाले दलों के साथ समझौते किए हैं। असल बात अंडरस्टैंडिंग और वोटों के संतुलन की है। अगर दो दल एक–दूसरे के आधार में सेंध नहीं लगाते तो कोई समस्या नहीं आती। महाराष्ट्र में देखने की बात यह होगी कि तीनों सहयोगी दल एक–दूसरे के स्पेस का ख्याल रख पाते हैं या नहीं। इसी तरह तीनों दलों के नेताओं में कितना समन्वय रह पाता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। अभी तीनों का ही लक्ष्य बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना था, इसलिए उनमें आसानी से एकता बन गई लेकिन सरकार चलाने के क्रम में कई तरह के हित एक–दूसरे से टकराते हैं, जिन्हें साध कर रखना एक चुनौती होगी। तीनों पार्टियों को अपना घर बचाए रखने के लिए सचेत रहना होगा। महाराष्ट्र का यह प्रयोग राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

संभव है यह बिहार को सीधे प्रभावित करे। जब महाराष्ट्र में 30 साल पुराना बीजेपी–शिवसेना गठबंधन टूट सकता है तो बिहार का जोड़ तो शुरू से कच्चा माना जाता रहा है। हालांकि वहां सीएम पद को लेकर अलग सुर नहीं सुनाई देते। महाराष्ट्र प्रकरण में एक नई बात यह है कि शरद पवार एक बड़े समन्वयक के रूप में उभरे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण विपक्ष को एकसूत्र में बांधने की जरूरत राहुल गांधी नहीं पूरी कर पाए। संभव है, शरद पवार पूरे अपोजिशन की एकजुटता का जरिया बनें। जो भी हो, अभी महाराष्ट्र की नई सरकार को जनहित में तेजी से कदम उठाने होंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो वादे किए गए हैं, उनको पूरा करना होगा। सारे राजनीतिक प्रयोगों की सफलता अंततरू गवर्नेंस पर ही निर्भर करती है।

लालच

मोनी मोहन भट्टाचार्य

धर्म-दर्शन

रावण, श्रीलंका का शक्तिशाली राजा और एक महान योद्धा, अपने चरम अहंकार के कारण अपने ही पतन का कारण बना। दुर्योधन, हस्तिनापुर का एक और पराक्रमी राजा, अंततः लालच और ईर्ष्या के परिणामस्वरूप कुरुक्षेत्र के मैदान के युद्ध में मारा गया। राजा बाली को विष्णु द्वारा अपने एक बौना, वामन अवतार रूप में, प्रेतलोक में निर्वासित किया गया था, राजा के अंधाधुंध दान के ही कारण। ऊपर उल्लेखित पात्र कोई साधारण लोग नहीं थे, फिर भी वे अपने–अपने पात्रों के चरित्रों के लुभावने जुनून से अभिभूत थे, इस हद तक कि बार–बार नेक सलाह मिलने पर भी वे खुद को लौटा नहीं पाए। यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि दानशीलता को नकारात्मक गुण नहीं माना जाता है, मगर अत्यधिक दानशीलता का कर्म संभवतः एक दबा हुआ अहम जरूर लाता है दिमाग में, जो कि किसी के पतन का जिम्मेदार हो सकता है।

संपादकीय

सबसे महंगा शहर

मुंबई शहर विदेशियों के रहने के लिहाज से भारत में सबसे महंगा है। दिल्ली इस मामले में दूसरे तो चेन्नै और बेंगलुरु तीसरे–चौथे नंबर पर आते हैं। यह रैंकिंग ग्लोबल कंसल्टिंग लीडर मर्सर के एक हालिया सर्वे से मिली है। नजर को भारत से ऊपर ले जाकर पूरी दुनिया के शहरों का जायजा लें तो बाहर से आकर रह रहे लोगों के आम रहन–सहन के खर्चे के लिहाज से पहले नंबर पर हांगकांग, दूसरे पर टोक्यो, तीसरे पर सिंगापुर और चौथे पर सियोल दिखता है। दिलचस्प बात यह कि ये सारे शहर एशियाई हैं। मुंबई और दिल्ली इस सूची में क्रमशरू 67वें और 118वें स्थान पर हैं। यह सर्वे यूं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर्मचारियों और विशेषज्ञों पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखकर करवाया जाता है, पर इससे दुनिया में विभिन्न शहरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को समझने में भी मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था के ग्लोबल दौर में जैसे–जैसे कारोबार देश की सीमाओं से ऊपर उठता गया वैसे–वैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारियों को एक देश से दूसरे देश भेजने का चलन भी तेज होता गया। अभी ज्यादातर कंपनियों में ऐसे कर्मचारी अच्छी–खासी संख्या में होते हैं जिन्हें विदेशों में रहकर कंपनी के प्रॉजेक्ट संचालित करने होते हैं। इसके अलावा उन्हें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और पेशेवरों की अंशकालिक सेवाएं भी लेनी होती हैं। इतने बड़े पैमाने के मैन–मैनेजमेंट के लिए इस बात की सटीक समझ होना जरूरी है कि किस शहर में किस स्तर के रहन–सहन पर कितना खर्चा आएगा।

जरूरी है कि हम अपने शहरों की उन विशेषताओं पर ध्यान दें और उन्हें बनाए रखते हुए न सिर्फ विदेशियों बल्कि अपने लोगों के लिए भी उन्हें अधिक आरामदेह बनाने की कोशिश करें।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसकी व्यापारिक और कूटनीतिक घेरेबंदी का नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है, हालांकि जब–तब वह भारत को इसमें भागीदार भी बनाना चाहता है।

दबदबा बनाम व्यापार

श्रद्धा वर्मा

जी–20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह जी–7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इसका मकसद विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाना और दुनिया की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना है। 2008 में जब दुनिया मंदी की गिरफ्त में आई थी तो उससे बाहर निकलने में केंद्रीय भूमिका जी–20 ने ही निभाई थी। लेकिन उस वक्त प्रमुख देशों के नेताओं में जो तालमेल दिखा था, वह आज सिरे से नदारद है।

लगभग सारे ताकतवर देशों के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। हर किसी को अपनी ही पड़ी है। मिलकर चलने की बात सिर्फ रवायती बयानों में नजर आती है। दुनिया का 15 फीसदी जीडीपी अकेले संभाल रहे अमेरिका ने संरक्षणवाद की नीति अपना ली है और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर नंबर दो मुल्क चीन का कारोबार बर्बाद करने पर आमादा दिख रहा है। इसके लिए चीन के खिलाफ उसने एकतरफा ट्रेड वॉर छेड़ रखा

है। वह यह सुनने को भी राजी नहीं है कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसकी व्यापारिक और कूटनीतिक घेरेबंदी का नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है, हालांकि जब–तब वह भारत को इसमें भागीदार भी बनाना चाहता है।

जी–20 की बैठक से तुरंत पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की भारत यात्रा संयोग नहीं है। जापान में ही जी–20 के किनारे पर होने वाली भारत, चीन और रूस के नेताओं की मुलाकात ने उसे परेशान कर दिया है। चीन ने संकेत दिया है कि ये तीनों देश अमेरिका की कारोबारी तानाशाही से मुकाबले के लिए साझा रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में संभव है, भारत को कुछ रियायतें देकर अमेरिका आपसी रिश्तों में आए ठंडेपन को दूर करने की कोशिश करे। दरअसल अमेरिका भारत और रूस के बीच एस–400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर हुई डील से नाखुश है। द्विपक्षीय व्यापार के स्तर पर भी कुछ तकरार है।

अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर शुल्क लगाने के बाद भारत ने भी उसके 28 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ईरान से तेल खरीद पर रोक का मुद्दा भी एक बड़ी अड़चन है। अमेरिका इन मुद्दों पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इतनी तनातनी और अविश्वास ने जी–20 की सफलता पर इसकी शुरुआत से पहले ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। जब अलग–अलग देश अपने हिसाब से समझौते करेंगे तो फिर सामूहिक प्रयासों का अर्थ क्या बचेगा। अभी अमेरिकी उठापटक के चलते डब्ल्यूटीओ जैसे व्यापारिक मंच भी अप्रासंगिक होकर रह गए हैं। ऐसे में डर है कि कहीं यह सम्मेलन रस्म–अदायगी ही बनकर न रह जाए।

अष्टयोग-4881

		4	6		1	2
2	33		36		27	5
7		5		3		
	42		25	1	22	6
	6			2		4
6	36		32		34	
1		3	4	5		7

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4880 का हल

3	7	6	1	2	4	5
2	33	1	23	6	33	6
5	7	2	4	1	6	3
4	40	4	27	4	24	4
7	6	5	4	3	2	1
6	37	7	38	7	33	2
1	2	3	4	5	6	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

पढ़ाई की मिसाल

भुवेंद्र त्यागी। हमारी कामवाली बाई कभी अडवांस सैलरी नहीं मांगती। उसे हमने कुछ महीने पहले ही रखा है, क्योंकि पहली वाली बाई लातूर की थी और वह अपने गांव लौट गई। इस बाई को हम हर महीने पहली तारीख को ही पगार दे देते हैं, तो वह बहुत खुश होकर ले जाती है। इस बार उसने महीने के आखिरी हफ्ते में ही कहा कि उसे पैसों की जरूरत है। पत्नी ने यह सोचकर उसे पगार दे दी कि उसका कोई जरूरी खर्चा आ गया होगा। वह संकोच से खड़ी रही। पूछने पर बोली कि पगार नहीं, उधार चाहिए। 'इससे भी ज्यादा?', पत्नी ने पूछा। वह बोली, 'हां। बेटे के कॉलेज में भरने हैं। मैंने कब्बी किसी से उधार नहीं मांगा३, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी।' कितना चाहिए, पूछने पर उसने कहा, 'दस हज्जार।' उसने कभी सौ रुपये भी नहीं मांगे थे इससे पहले।

उसका कहना था कि बड़ा बेटा तो 'पार लग गया' है, एक साल में होटल में काम करने लगेगा। छोटे बेटे के लिए अभी मेहनत करनी है। वह साइंस पढ़ रहा है। उसे इंजिनियर बनाना है। बेटा बोला था कि इसके लिए कोचिंग करना जरूरी है। इसी वास्ते रुपये चाहिए।